LOK SABHA

Monday, December 18, 1967/Agrahayana 27, 1889 (Saka)

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[MR. SPEAKER *in the Chair*]

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

भूतपूर्व नरेशों की निजी थैलियां समाप्त करने के बारे में सिंगापुर में भारतीय उच्चायुक्त का वक्तव्य

*721. श्री शशि भूषण वाजपेयी : क्या वैदेशिक-कार्य यह बतानें की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान सिंगापुर में भारतीय उच्चायुक्त के इस वक्तव्य की ओर दिलाया गया है कि निजी थैलियां तथा नरेशों के विशेषाधिकार समाप्त कर देने से भारत में पूंजी लगानें वाले विदेशी मित्रों के रवैये पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ;

(ग) क्या भारतीय राजदूतों को हमारी आन्तरिक नीतियों के सम्बन्ध में ऐसे विवादास्पद मामले उठाने की अनुमति दी जाती है; और

(घ) यदि नहीं, तो इस सम्बन्ध में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) से (घ). सरकार ने 'एजेंसे फ्रांस प्रेसे' की रिपोर्ट पूरी देखी है। इस सारी रिपोर्ट को पढ़नें के बाद, और सम्बद्ध अधिकारी ने सफाई में जो उत्तर दिया है, उसे देखते हुए यह पता चलता है कि उसनें इतनी अखरने वाली बात नहीं कही थी जितनी कि वह अविवेकपूर्ण थी । फिर भी, इस अधिकारी को समुचित चेतावनी दे दी गई है और कह दिया गया है कि वह ऐसे सार्वजनिक वक्तव्य न दें जिन्हें भारत सरकार की नीतियों और विचाराधीन कार्रवाइयों की आलोचना समझे जाने की जरा सी भी गुंजाइश हो ।

श्री शशि भूषण वाजपेयी : किसी राजा का पुत्र या किसी बैंकर का लड़का या किसी होर्डर का लड़का राजदूत बन जाए और उसके बाद यह कहे कि प्रिवी पर्स अगर हिन्दुस्तान में खत्म हो जायेगा तो इंटरनेशनल रिलेशंज खराब हो जायेंगे या यह कहे कि अगर बैंक नेशनालइज हो जायेंगे तो इंटरनेशनल रिलेशन खराब हो जायेंगे तो इसकी अनुमति आप किस प्रकार दे सकेंगे। मैं यह भी जानना चाहता हूं कि उन के खिलाफ क्या एक्शन लिया गया है ?

श्री ब० रा० भगत : जैसे कहा है मैंनें अपने उत्तर में उनको चेतावनी दी गई कि ऐसी बातें वह सार्वजनिक रूप से न कहा करें···

श्री शिव नारायण : कह दी है उन्होंने ।

श्री ब० रा० भगत : कह दी है तभी तो चेतावनी दी गई है और अगर न कही होती [तो चेतावनी क्यों देने की जरूरत पड़ती। सरकारी मुलाजिमों के लिए कुछ नियम भी बने हुए हैं कि सरकार की जो नीतियां हैं या सरकार जिन नीतियों पर अमल करने जा रही है उनके बारे में वे टिप्पणी न करें। ऐसे वक्तव्य न दें जिन से राजनीतिक

प्रतिक्रिया की आशंका हो। उनकी इन मामलों में व्यक्तिगत राय कुछ भी हो सकती है और उसको रखने के लिए वे स्वतन्त्र हैं। राजा का पुत्र हो चाहे वह उसकी व्यक्तिगत राय कुछ भी हो सकती है लेकिन सार्वजनिक रूप से या आधिकारिक रूप से वे अपनी राय नहीं दे सकते हैं या दखल नहीं दे सकते हैं।

SHRI R. K. SINHA: It is seen that at times our representatives abroad, because of a sense of duty, have to come out with certain statements. That is one thing. But sometimes our representatives cross certain prescribed limits and this brings into controversy our national and international policies. Will the Government, therefore, lay down a code of conduct for all employees abroad that they should not cross certain limits in giving out statements to the press?

SHRI B. R. BHAGAT: There is a code of conduct, Sir.

श्री अटल बिहारी बाजपेयी : मंत्री महोदय ने अपने उत्तर में कहा है कि हमारे सिंगापुर स्थित हाई कमिश्नर के द्वारा जो सफाई दी गई है उसको देखते हुए सरकार कोई और कार्रवाई करना आवश्यक नहीं समझती है। जहां तक हमारे इन हाई कमिश्नर का सवाल है वह एक कायदे के आदमी मालूम होते हैं। मैं जानना चाहता हूं कि कौन सा मौका था जिस पर उन्हें इस तरह का वक्तव्य देना पड़ा और उन्होंने अपनी सफाई में क्या कहा है? क्या उन्होंने यह कहा है कि उन्होंने अपने व्यक्तिगत विचार प्रकट किये हैं या सरकार की नीति को प्रभावित करने के लिए उन्होंने वक्तव्य दिया है?

श्री ब० रा० भगत: उन्होंने प्रेस के लोगों से कुछ बातचीत की। कोई वक्तव्य ऐसा नहीं दिया लेकिन बातचीत की और उन्होंने बातचीत के दौरान यह कहा भी कि यह उनकी व्यक्तिगत राय है। लेकिन वह बात छपी अखबारों में। इसलिए उनको यह करना नहीं चाहिये था कि सरकार की जो नीतियां हैं उनके बारे में वह व्यक्तिगत राय दें और उन बातों की चर्चा प्रेस में हो। इस वास्ते उनको चेतावनी दी है कि आइंदा कोई ऐसी बात न किया करें।

श्री मनु भाई पटेल : जो बयान उन्होंने दिया है वह जो हमारी बुनियादी नीति है उसके खिलाफ है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या उनको चेतावनी देना काफी था, हमारी सावरेनटी है उस पर हमला हो तो क्या चेतावनी देना काफी है?

श्री ब० रा० भगत : यह अधिकारी पुराने हैं। बीस साल से फारेन सर्विस में हैं। उनका अच्छा रिकार्ड अभी तक रहा है। यह एक ऐसी बात हुई है कि जिस के लिए यह उचित समझा गया कि उनको चेतावनी दी जाए और आगे से वह इस तरह की बात न कहें।

SHRI SWELL : Sir, very often our representatives abroad are subjected to questions about the affairs in the country about which perhaps the Government has not taken any decision. What do the Government expect these people to do under those circumstances? Are they expected to keep silent like wood and stone or are they expected to explain the policy of the country to those people?

SHRI B. R. BHAGAT: They are expected to explain the policy of the country, not to keep silent, if they are asked specifically. Even if certain decisions are not taken they can explain why decisions are not taken and not say anything for or against it.

SHRI D. C. SHARMA: Evidently the High Commissioner has functioned more as a price of some State—I do not know to which State he belongs—than as the High Commissioner of the sovereign democratic republic of India which pursues certain policies in the national field and also in the international field. In the light of this, may I know what kind of warning has been given to him? There are so many types of warning. There is warning, displeasure, suspension and dismissal. What kind of warning has been given to him? I think that a warning is absolutely inadequate for the criticism that he has offered of the poli-

cies of the Indian Government, and such as person I do not think deserves to be our High Commissioner anywhere.

SHRI B. R. BHAGAT: He has been warned that he has been expressing personal views in his official capacity.

SHRI C. C. DESAI: I think the function of a High Commissioner is to communicate to the Government here and to the country also what the reaction on broad policies is in the foreign countries. What is wrong in his telling to the Government and to the country here that by pursuit of this policy the confidence in the Government's credit would be shaken in the foreign countries ? Secondly, where is the objection? Why is this an act of indiscretion when similar statements are being made by the very gentleman sitting next to the hon. Minister, when the same thing has been done by Shri Gaikwad, Minister of Health in the Gujarat Government and when the same thing is done by Shri Karan Singh? Where is the indiscretion on the part of this particular person.

SHRI B. R. BHAGAT: The hon. Member has been a very distinguished High Commissioner.....(*Interruption*).

MR. SPEAKER: Order, order. I think the hon. Minister must reply and not any other hon. Member.

SHRI B. R. BHAGAT: The hon. Member has been a very distinguished High Commissioner himself, and I think more than anyone else he realises the distinction between communicating a personal view publicly and a communication with the Government. He cannot compare it with an opinion expressed by a political personality. I think that also he realises. He has been a very distinguished civil servant also. A civil servant has certain obligations. A person in politics, whether he occupies an important position or not, is free to express his view.

SHRI INDRAJIT GUPTA: The hon. Minister has stated that it is the duty of our foreign envoys to explain or interpret our policy abroad. Now, may I know whether his attention has been drawn to a news report this morning which quotes our *charge d' affaires* in Washington, Shri Banerjee, as having stated that border settlement with China is an impossibility. Now, however intrasigent and hostile the present Chinese attitude may be, I would like to know whether it is government's policy that border settlement with China is an impossible question?

MR. SPEAKER: This question relates to Singapore.

SHRI INDRAJIT GUPTA : Part (c) of the question is whether our envoys are allowed to raise controversial points. I want to know whether his attention has been drawn to this and, if so, the reaction of the government—is this going to be our declared policy.

SHRI B. R. BHAGAT: That report has appeared this morning. Certainly, the hon. Member cannot expect the government to comment on this without a clarification from the person as to what he has actually stated.

SHRI INDRAJIT GUPTA: But is it our declared policy that a peaceful settlement of the border question with China is an impossibility?

SHRI B. R. BHAGAT: As far as the policy of the Government of India is concerned, it is well-known and it has been stated many times. But the hon. Member is asking for information on the statement made by the *charge d' affaires*.

SHRI ANANTRAO PATIL: May I know from the hon. Minister whether it will be useful or not to conduct refresher courses for our envoys before they are appointed?

SHRI B. R. BHAGAT: It is done. Whenever a person joins the Foreign Office he is given a very thorough training.

श्री मधु लिमये : हमारे संविधान में 1950 में कई बातें मन्जूर की गई। जैसे माननीय सदस्य, श्री देसाई और लोबो प्रभु जैसे लोगों के लिए अनुच्छेद 314 रखा गया। उसी तरह राजा-महाराजाओं के लिए भी कुछ उपबन्ध किये गये । मैं सरकार से इस बात का खुलासा चाहता हूं कि जब इस तरह की बात राजदूतों के द्वारा कही जाती है, तो क्या इसका मतलब यह नहीं है कि विदेशियों को उकसाया जा रहा है कि वे यहां पर पूंजी

न लगायें; यदि हां, तो क्या मंत्री महोदय इस राजदूत को यह सलाह देंगे कि वह तत्काल इस्तीफा दे दें ? हो सकता है कि हमारे राजा-महाराजा उन को लोक सभा का चुनाव लड़ने के लिए टिकट दे दें, वह चुनाव लड़ें और फिर अपना काम करें। जब मेरे प्रस्ताव के सिद्धान्त को सरकार ने स्वीकार कर लिया है, तो अब यह सरकारी नीति हो गई है कि कि राजा-महाराजा के निजी कोषों को समाप्त कर दिया जाये । ऐसी हालत में किसी भी सरकारी कर्मचारी को—और राजदूत भी सरकारी कर्मचारी होता है—सरकारी नीति के विरुद्ध बोलने या काम करने की छूट नहीं होनी चाहिए। वह अपने पद से इस्तीफा दे दें, चुनाव लड़ें और फिर लोक सभा में वह अपनी बात रखें।

THE PRIME MINISTER, MINISTER OF ATOMIC ENERGY, MINISTER OF PLANNING AND MINISTER OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRIMATI INDIRA GANDHI): It is hardly a question.

SHRI PILOO MODY: I would like to know first of all whether the government has taken any final decision in the matter of privy purses and privileges or the effect that it would have on the flow of foreign capital in this country. If they have not taken any posture on that question, then I would like to know from the hon. Minister what would have been his reply to a question such as the one put to the High Commissioner in Singapore?

SHRIMATI INDIRA GANDHI: The government has not taken a final decision. As hon. Members are aware, the Home Minister was to discuss the implementation of the resolution passed by the All India Congress Committee with the Princes.

श्री मधु लिमये : सरकार ने प्रिंसिपल तो मान लिया है। क्या आप इससे भी भाग रही हैं ?

SHRI PILOO MODY: In that case, what was the reply that he could have given?

MR. SPEAKER: The same reply could have been given.

AN HON. MEMBER: He should have kept quiet.

SHRI V. KRISHNAMOORTHI: In view of the deplorable conduct on the part of the High Commissioner in Singapore and also the discussions here, may I know from the hon. Prime Minister whether the government will recall him and replace him?

MR. SPEAKER : That was exactly the question asked by Shri Limaye. It is becoming repetitive.

SHRI V. KRISHNAMOORTHI: The Prime Minister is getting up to answer. Mere warning is not sufficient. I want to know whether he will be recalled.

SHRIMATI INDIRA GANDHI: I think 'deplorable' is a rather strong word. As the Minister said, the High Commissioner has committed an indiscretion and he has been duly warned. We certainly hope that our Ambassadors will not make unnecessary statements.

Tibetan Refugees

*723. SHRI M. R. MASANI: Will the Minister of EXTERNAL AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether the attention of Government has been drawn to a report in the *Times*, London of the 2nd September, 1967 carrying an interview with Mr. Keith Satterthwaite, voluntary worker with Tibetan refuges in India, who claimed that he had been forced out from the Tibetan craft community with which he was working by the Indian officials as part of a general policy of hindering and stopping voluntary work by foreign nationals among Tibetan refugees;

(b) whether the above facts are correct; and

(c) whether it is a fact that Government have initiated a general policy of stopping work by foreign nationals among Tibetan refugees in this country and, if so, the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI B. R. BHAGAT): (a) Yes, Sir.

(b) and (c). Mr. Keith Satterthwaite, a farm worker from England, was reported to